इकाई 28 ट्रेड यूनियन और किसान आंदोलन : 1920 और 30 के दशक

इकाई की रूपरेखा

28.0 उद्देश्य

इस इकाई का उद्देश्य आपके सामने 1920 और 1930 के दशकों के दौरान भारत में "ट्रेड यूनियन और किसान आन्दोलन" के विकास का संक्षिप्त इतिहास प्रस्तुत करना है । इस इकाई को पढ़ने के बाद आप :

- **श्रमिकों की दशा के बारे में जान सकेंगे,**
- **ट्रेड यूनियनवाद का अर्थ, इसका आरंभिक इतिहास और आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना के विषय में बता सकेंगे,**
- **ट्रेड यूनियन आन्दोलन के विकास की प्रक्रिया और बाद में उनके बीच हुए विभाजन के विषय में जान सकेंगे,**
- **किसानों की कठिनाइयों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, और**
- **यह व्याख्या कर सकेंगे कि किसान आन्दोलन किस प्रकार देश के विभिन्न भागों में उभरे और किस प्रकार वे किसान सभा में संगठित हुए ।**

28.1 प्रस्तावना

आपने खण्ड दो की इकाई-7 में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में हुए किसान और श्रमिक वर्ग के आन्दोलनों के विषय में पढ़ा था । इस इकाई के अन्तर्गत हम आपको 1920 और 1930 के दशकों के दौरान हुए ट्रेड यूनियन और किसान आन्दोलनों के विकास के विषय में बताएंगे । पहले हम ट्रेड

यूनियन आन्दोलन पर और उसके बाद किसान आन्दोलन पर विचार करेंगे । आप पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में औपनिवेशिक सरकार, ज़मींदार और मिल मालिकों के शोषण और उत्पीड़न के कारण किसानों और मज़दूरों ने आन्दोलन किये । आप अब समझ सकेंगे कि 20वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में किस प्रकार इन आन्दोलनों ने धीरे-धीरे संगठित रूप धारण किया और औपनिवेशिक साम्राज्य पर अपनी नीतियां बदलने के लिए दबाव डाला । इस काल के श्रमिक वर्ग की प्रकृति और किसान आन्दोलनों में हुए इन परिवर्तनों को समझने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए :

- राष्ट्रीय आन्दोलन में नयी प्रवृत्तियों का उभरना—विशेषकर जन-राजनीति और जन-संगठनों की तरफ झुकाव ।
- प्रथम विश्वयुद्ध के आर्थिक, सामाजिक परिणाम, जिन्होंने भारतीयों के विभिन्न वर्गों पर विपरीत प्रभाव डाला । और
- बोल्शेविक रूस का प्रभाव और भारत में समाजवादी विचारों का विकास ।

इन सभी कारणों से भारत में श्रमिक वर्ग और किसान आन्दोलनों का विकास हुआ । इन आन्दोलनों की प्रकृति उन पुराने आन्दोलनों से, जिनकी हम चर्चा कर चुके हैं, भिन्न थी ।

28.2 श्रमिकों की दशा

अब हम संक्षेप में श्रमिकों की दशा का वर्णन करेंगे । इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि भारत में ट्रेड यूनियनों की स्थापना क्यों हुई । भारत में सूती वस्त्र उद्योग का मुख्य केन्द्र बम्बई तथा जूट और चाय का मुख्य केन्द्र बंगाल था । यहां श्रमिकों की जनसंख्या भारत में सबसे अधिक थी । श्रमिकों के रहने और कार्य करने की परिस्थितियां बहुत शोचनीय थीं । वे एक दिन में 15-16 घंटे से लेकर 18 घंटे तक काम करते थे । अवकाश की कोई व्यवस्था नहीं थी । श्रमिकों को ठेकेदारों (सरदार) को रिश्वत देनी पड़ती थी, जिन पर उनकी आजीविका निर्भर करती थी । वे अंधेरी और अस्वास्थ्यकर बस्तियों में रहते थे । जहां पानी और सफ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं थी ।

कोयला खानों के मज़दूरों की दशा और भी अधिक शोचनीय थी । झरिया और गिरिडिह की कोयला खानों के श्रमिकों के काम के घंटे प्रातः 6 बजे से सांय 6 बजे तक थे । स्त्रियां और बच्चे भूमिगत खानों में काम करते थे । वहां प्रायः दुर्घटनाएं हुआ करती थीं । 1923 के बाद ही सरकार ने दुर्घटना बीमा योजना शुरू की थी । इसके बाद भी श्रमिकों को दुर्घटनाओं के मुआवज़े की रकम लेने के लिए भी परेशानी उठानी पड़ती थी । श्रमिकों को मज़दूरी कम दी जाती थी, जिससे मालिकों को अधिक से अधिक लाभ हो सके । रॉयल कमीशन आन लेबर ने स्पष्ट किया कि मद्रास और कानपुर में मज़दूरी सबसे कम और बम्बई में सबसे ज़्यादा है । श्रमिकों द्वारा नुकसान करने, देर से आने और कम उत्पादन के लिए कई सालों तक जुर्माना वसूल किया जाता था । श्रमिक ऋणग्रस्त रहते थे । उन्हें प्रायः काबुली महाजनों का सहारा लेना पड़ता था । ये महाजन ब्याज की ऊँची दरें वसूल करते थे । भविष्य निधि और पेंशन की कोई व्यवस्था नहीं थी । वृद्ध होने पर श्रमिकों को काम से हाथ धोना पड़ता था । अतः उन्हें अपने भरण-पोषण (जीवन-निर्वाह) के लिए अपने बच्चों या रिश्तेदारों पर निर्भर रहना पड़ता था ।

बोध प्रश्न 1

अपने उत्तर नीचे दिए गए स्थान में लिखिए ।

1) श्रमिकों की शोचनीय दशा के विषय में पांच पंक्तियों में लिखिए ।

....

....

....

....

....

2) नीचे दिए गए प्रत्येक वाक्य का उत्तर हाँ या नहीं में दीजिए ।

क) बम्बई भारत के जूट उद्योग का मुख्य केन्द्र था । ( )

ख) कलकत्ता और बम्बई में श्रमिकों की जनसंख्या सबसे अधिक थी । ( )

ग) श्रमिकों को प्रत्येक दिन 15 से 16 घंटे काम करना पड़ता था । ( )

घ) रॉयल कमीशन आन लेबर की नियुक्ति श्रमिकों की दशा की जांच-पड़ताल करने के लिए हुई थी । ( )

ङ) श्रमिकों को हड़ताल करने का अधिकार था । ( )

च) श्रमिकों के लिए वृद्धावस्था-पेंशन की व्यवस्था थी । ( )

28.3 ट्रेड यूनियनवाद का उदय

आइये देखें कि शोषण के विरुद्ध संघर्ष के लिए श्रमिक किस प्रकार संगठित हुए । वास्तव में ट्रेड यूनियनवाद का उदय श्रमिक वर्ग के आन्दोलन में एक नये युग का प्रतीक था ।

28.3.1 ट्रेड यूनियनवाद का अर्थ

ट्रेड यूनियनें जोकि आज बहुत प्रचलित हैं, श्रमिकों की ऐसी संस्थाएं हैं जिनका उद्देश्य फैक्टरियों में काम करने वाले श्रमिकों की दशा सुधारना है। 19वीं शताब्दी में भारत में फैक्टरियों और मिलों की स्थापना होने पर सैकड़ों की संख्या में श्रमिक प्रतिदिन इकट्ठे काम करने लगे और रोज़ मिलने लगे। इससे उन्हें अपनी समस्याओं की चर्चा करने और अपने विचार मालिकों के सामने रखने का अवसर मिला । अधिकांश श्रमिक अशिक्षित थे । आरम्भ में उनका ट्रेड यूनियन बनाने और स्वयं को संगठित करने का विचार नहीं था । अधिकतर बुद्धिजीवियों ने उन्हें शिक्षित किया और ट्रेड यूनियनों में संगठित किया । ये लोग प्रायः यूनियनों के नेता होते थे ।

28.3.2 आरंभिक इतिहास

जैसाकि हम पहले बता चुके हैं, कुछ व्यक्ति श्रमिकों की शोचनीय दशा देखकर उनकी काम करने की परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए आगे आए । उदाहरणस्वरूप ब्रह्म समाज के एक आमूल परिवर्तनवादी (Radical Brahmo) शशिपाड़ा बनर्जी ने कार्यरत व्यक्तियों का क्लब बनाया । उन्होंने 1874 में "भारत श्रमजीवी" (भारतीय श्रमिक) नामक अख़बार प्रकाशित किया और जूट मिल के श्रमिकों में शिक्षा का प्रसार करने के लिए रात्रिकालीन स्कूलों की व्यवस्था की । लेकिन उन्होंने ट्रेड यूनियन की स्थापना नहीं की । इसी प्रकार बम्बई में एन. एम. लोंखडे ने 1880 में 'दीनबन्धु' नामक साप्ताहिक पत्रिका आरंभ की तथा 1890 में 'बम्बई मिल हेंड्स एसोसिएशन' की भी स्थापना की । यद्यपि यह संस्था ट्रेड यूनियन नहीं थी, फिर भी इसने निम्नलिखित मागे पेश कीं ।

- काम के घंटों में कमी ।
- साप्ताहिक अवकाश और
- फैक्टरियों में काम के दौरान घायल हुए श्रमिकों को मुआवज़ा ।

अप्रैल 1918 में ऐनीबेसेन्ट के निकट सहयोगी बी. वी. वाडिया ने 'मद्रास लेबर यूनियन' की स्थापना की । यह भारत की पहली ट्रेड यूनियन थी । 1918 में मोहन दास करमचन्द गांधी ने अहमदाबाद के सूती कपड़ा उद्योग में श्रमिकों की हड़ताल का नेतृत्व किया । गांधी जी ने अपनी आत्मकथा "दी स्टोरी ऑफ़ माइ एक्सपेरीमेंट्स विद ट्रुथ" (The Story of My Experiments With Truth) में श्रमिकों की दशा का उल्लेख करते हुए लिखा है कि "उनकी मज़दूरी कम थी और इसमें वृद्धि के लिए श्रमिक बहुत समय से संघर्ष कर रहे थे ।"

गांधीजी ने मिल मालिकों से अनुरोध किया कि वे मामले मध्यस्थता के लिए भेज दें । परन्तु मिल मालिकों ने इन्कार कर दिया । तब गांधी जी ने श्रमिकों को हड़ताल करने की सलाह दी । हड़ताल 21 दिन तक जारी रही। गांधी जी ने उपवास शुरू किया लेकिन तीन दिन बाद ही समझौता हो गया। 1920 में गाधी जी ने 'मजूर महाजन संघ' की स्थापना की, जिसका उद्देश्य श्रमिकों और उनके मालिकों के बीच शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना और मध्यस्थता तथा समाज सेवा करना था ।

23.3.3 ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना

ऊपर बताए गए प्रयत्नों से ट्रेड यूनियनवाद धीरे-धीरे लोकप्रिय होने लगा । 1919-1920 में कानपुर, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, जमशेदपुर और अहमदाबाद जैसे औद्योगिक केन्द्रों में अनेकों हड़तालें हुई । हज़ारों श्रमिकों ने इन हड़तालों में भाग लिया । इस पृष्ठभूमि में 1920 में बम्बई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई । लाला लाजपतराय ने इस के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की । इसमें मोतीलाल नेहरू, ऐनीबेसैन्ट, सी. एफ. एंड्रयूज़, बी. वी. वाडिया और एन. एम. जोशी जैसे प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं और ट्रेड यूनियनवादियों ने भाग लिया । दी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भारतीय श्रमिकों का प्रधान संगठन था ।

यद्यपि 1920 के दशक में कई बार हड़तालें होती रहती थीं परन्तु श्रमिकों के बीच ट्रेड यूनियनवाद के विकास की गति धीमी थी । रॉयल कमीशन आन लेबर ने इसके दो कारण बताए :

i) भाषा और साम्प्रदायिक भिन्नता ऐसे कारक थे, जो श्रमिकों की एकता में बाधक थे । उदाहरण के लिए बंगाल जूट मिल में अधिकतर श्रमिक बिहार और यू. पी. (संयुक्त प्रान्त) से आए थे । बंगाली श्रमिकों की संख्या कम थी ।

ii) ठेकेदारों तथा मालिकों ने ट्रेड यूनियनों के विकास का विरोध किया ।

iii) 1929 में केवल 51 यूनियनें थीं । 190,436 सदस्य ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से संबद्ध थे । लेकिन अभी भी बहुत से श्रमिक ट्रेड यूनियनों में संगठित नहीं थे क्योंकि उन्हें नौकरी से निकाले जाने का डर था ।

बोध प्रश्न 2

अपने उत्तर नीचे दिए गए स्थान में लिखिए ।

1) ट्रेड यूनियन क्या है ? उत्तर लगभग 25 शब्दों में दीजिए ।

....

....

....

2) क्या ट्रेड यूनियन श्रमिकों के लिए लाभदायक है ? 25 शब्दों में उत्तर दीजिए ।

....

....

....

3) श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए किए गए आरंभिक प्रयासों के विषय में पांच पंक्तियां लिखिए ।

....

....

....

....

....

....

4) ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई ? 50 शब्दों में उत्तर दीजिए ।

....

....

....

....

....

....

28.4 ट्रेड यूनियनों का विकास

इन सभी रुकावटों के बावजूद ट्रेड यूनियन आन्दोलन श्रमिकों के बीच लोकप्रियता प्राप्त कर रहा था । इसका मुख्य कारण श्रमिकों की अनेक तकलीफें थीं, जैसे काम के अत्यधिक घंटे, अस्वास्थ्यकर आवास व्यवस्था, अपर्याप्त मज़दूरी, नौकरी से निकाला जाना आदि । उन्होंने सहायता के लिए "बाहरी व्यक्तियों" का सहारा लिया । ये बाहरी व्यक्ति राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट और समाजवादी तथा कुछ निर्दलीय भी होते थे । ये बाहरी व्यक्ति श्रमिकों की सभाएं आयोजित करते थे, मालिकों को सम्बोधित कर याचिकाएं लिखते थे और मांग पत्र तैयार करते थे । वे श्रमिकों को ट्रेड यूनियनों में संगठित करते थे तथा ये ट्रेड यूनियनें ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से सम्बद्ध थीं । जब मालिक उनकी मांगे अस्वीकार कर देते थे, तब श्रमिक हड़ताल करते थे । प्रायः हड़ताल के दौरान ट्रेड यूनियनें श्रमिकों की आर्थिक सहायता करती थीं क्योंकि हड़ताल के दौरान श्रमिकों को मज़दूरी नहीं मिलती थी । हड़तालों के कारण श्रमिकों को बहुत अधिक परेशानियाँ उठानी पड़ती थीं । विशेषकर जब ये हड़तालें महीनों तक चलती थीं । इन परेशानियों के बावजूद भी फैक्टरियों में अनेक हड़तालें हुई । सरकारी कार्यालयों और व्यापारिक फर्मों के कर्मचारियों ने भी ट्रेड यूनियनें बनायीं और हड़तालें आयोजित कीं ।

अब हम इस काल में भारत में हुई कुछ हड़तालों के विषय में चर्चा करेंगे । भारत में बम्बई सूती कपड़ा मिलों का सबसे बड़ा केन्द्र था । इनमें से अधिकांश मिलें भारतीय पूंजीपतियों द्वारा स्थापित की गयी थीं । 1924 में बम्बई में 150,000 श्रमिकों की एक बड़ी हड़ताल हुई । हड़ताल का मुख्य कारण मज़दूरों को पिछले चार वर्षों से मिलने वाला बोनस इस वर्ष नहीं दिया जाना था । 1926 में एन. एम. जोशी की अध्यक्षता में 'टैक्सटाइल लेबर यूनियन' की स्थापना की गयी । अप्रैल 1928 में बम्बई में एक आम हड़ताल हुई । अधिकांश मिलों के श्रमिकों ने इस हड़ताल में भाग लिया । जब सरकार ने श्रमिकों की मांगों पर विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त की तब 9 अक्टूबर को हड़ताल समाप्त हो गयी । इस प्रकार हड़ताल ने सरकार को श्रमिकों और मालिकों के बीच हुए झगड़े में हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य किया ।

बंगाल की जूट मिलों पर अंग्रेज़ पूंजीपतियों का अधिकार था । यह बंगाल का सबसे बड़ा उद्योग था । बंगाल में 1921-29 के दौरान 592 औद्योगिक विवाद हुए । इनमें से 236, जूट मिलों में हुए । 1928 में हावड़ा जिले के बाउरिया में फोर्ट ग्लोस्टर मिल के श्रमिकों ने हड़ताल कर दी । यह हड़ताल बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यह 17 जुलाई से 31 दिसम्बर तक यानी लगभग 6 महीने चली । जवाहरलाल नेहरू ने इस हड़ताल के विषय में लिखा है कि—"बाउरिया का गांव हावड़ा शहर से 16 मील पर है ··· इस गांव और इसके आसपास के इलाके में फैक्टरी के ग़रीब श्रमिकों और बंगाल के बड़े जूट मालिकों के बीच भीषण संघर्ष हुआ । ··· उनमें से पंद्रह हज़ार व्यक्तियों ने इस संघर्ष को 6 महीने से भी अधिक समय तक ज़ारी रखा ।"

जुलाई 1929 में जूट मिलों में एक आम हड़ताल हुई । बंगाल कांग्रेस ने हड़ताल के प्रति सहानुभूति दिखायी । सरकार ने हस्तक्षेप किया और 16 अगस्त को हड़ताल समाप्त हो गयी ।

जमशेद जी टाटा ने भारत में जमशेदपुर में पहली आधुनिक स्टील फैक्टरी स्थापित की । लगभग 20 हज़ार श्रमिक इस फैक्टरी में काम करते थे । 1920 में श्रमिकों ने "लेबर एसोसिएशन" की स्थापना की । बड़ी संख्या में श्रमिकों के निकाले जाने के विरोध में टाटा स्टील फैक्टरी के श्रमिकों ने 1928 में एक आम हड़ताल की । यह हड़ताल 6 महीने से ज़्यादा चली । यद्यपि हड़ताल पूरी तरह सफल नहीं थी परन्तु मालिकों ने "लेबर ऐसोसिएशन" को मान्यता दे दी ।

इस काल के दौरान अहमदाबाद में मिल मालिकों द्वारा मज़दूरी में 20% कटौती किए जाने के विरोध में 64 कपड़ा मिलों में से 56 में आम हड़ताल हुई । मद्रास शहर भी ट्रेड यूनियन आन्दोलन का एक महत्वपूर्ण केन्द्र था । मद्रास में 1923 में सिंगारावेलू ने पहला "मई दिवस" मनाया ।

28.5 ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में विभाजन

अमेरिका में भीषण आर्थिक मंदी आरम्भ हुई और 1929 तक पूरे विश्व में फैल गयी । भारत में मंदी 1936 तक जारी रही । सैकड़ों फैक्टरियाँ बंद हो गयीं और हज़ारों श्रमिक रोज़गार से हाथ धो बैठे । यूनियनों की संख्या में भी कमी हुई ।

दुर्भाग्यवश इस काल के दौरान ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गयी। पहला विभाजन 1929 में हुआ। उस समय जवाहरलाल नेहरू ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इसका मुख्य मुद्दा था कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस अंग्रेज़ सरकार द्वारा नियुक्त रायल कमीशन आन लेबर का बहिष्कार करेगी या नहीं। उदारवादी इसमें शामिल होना चाहते थे, जबकि उग्रवादी इसका बहिष्कार करना चाहते थे। अंत में उदारवादियों ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस छोड़ दी और वी. वी. गिरि की अध्यक्षता में इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना की। 1931 में दूसरा विभाजन हुआ। कम्युनिस्टों ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को छोड़ दिया और रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। यह विभाजन उस समय हुआ जब मालिकों ने हज़ारों श्रमिकों को नौकरी से निकाल दिया था। विभाजनों के कारण ट्रेड यूनियन आन्दोलन कमज़ोर पड़ गया।

28.6 नया चरण

1935 के पश्चात् ट्रेड यूनियन आंदोलन का एक नया चरण आरंभ हुआ। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में पुनः एकता स्थापित हुई। 1936 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार आया। 1937 में कांग्रेस ने प्रान्तों में मंत्रिमंडलों की स्थापना की। कांग्रेस मंत्रिमंडलों की स्थापना से श्रमिकों की आकांक्षाएं बढ़ीं। 1936 और 1939 के बीच ट्रेड यूनियनों की संख्या दुगुनी हो गयी और इसके सदस्यों की संख्या भी काफ़ी बढ़ गयी। हड़तालों की संख्या 1936 में 157 से 1939 में 406 हो गयी। इनमें से प्रमुख हड़तालें 1935 में कलकत्ता में केसोराम कॉटन मिल्स और अहमदाबाद में टेक्सटाइल्स मिलों में, दिसम्बर 1936 से फ़रवरी 1937 तक बंगाल नागपुर रेलवे में हुईं। इसके अलावा 1936 के दौरान कलकत्ता जूट मिल्स और कानपुर टैक्सटाइल्स मिल्स में श्रमिकों तथा मालिकों के बीच अनेक झगड़े हुए जो आगामी वर्ष में पराकाष्ठा पर पहुंच गये तथा दोनों में व्यापक आम हड़तालें हुईं। इस समय की महत्वपूर्ण घटना दक्षिण पंथी और समाजवादियों द्वारा ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों को सामूहिक आन्दोलन के लिए एकताबद्ध करना था। दरअसल इस चरण में ही ट्रेड यूनियन आंदोलन का विकास हुआ।

बोध प्रश्न 3

1) ट्रेड यूनियन आन्दोलन श्रमिकों में लोकप्रिय क्यों हुआ ? बाहरी व्यक्तियों ने श्रमिकों की किस प्रकार सहायता की ? लगभग दस पंक्तियों में उत्तर दीजिये।

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

2) श्रमिकों पर आर्थिक मंदी का क्या प्रभाव पड़ा ? लगभग तीन पंक्तियों में उत्तर दीजिये।

....
....
....
....

3) 1937 के बाद ट्रेड यूनियन आन्दोलन के विकास का संक्षिप्त विवरण लगभग 100 शब्दों में दीजिये ।

....

....

....

....

....

....

....

....

....

28.7 किसानों की कठिनाइयाँ

1920 और 1930 के दशकों के दौरान भारत के विभिन्न भागों में अनेक किसान संघर्ष हुए । खंड 2 की इकाई-7 में आप पढ़ चुके हैं कि औपनिवेशिक शासन की स्थापना से किस प्रकार भारतीय कृषक वर्ग बुरी तरह से प्रभावित हुआ और उन्होंने इस शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाई । इस भाग में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार बदले हुए हालात भी किसानों का शोषण समाप्त नहीं कर पाये । वरन् यह वैसा ही बना रहा । लेकिन किसानों ने अपने अनुभव से यह सीखा कि उन्हें सरकार और ज़मींदारों की शक्ति के विरुद्ध असंगठित नहीं रहना चाहिए । एक ओर 20वीं शताब्दी में किसानों ने न केवल ताल्लुक़ेदारी और ज़मींदारी व्यवस्था की ज़्यादती के विरुद्ध विद्रोह किया, बल्कि किसान सभाओं जैसे किसान संगठनों की भी स्थापना की ।

भारत के विभिन्न भागों में शोषण के तरीक़ों में कुछ विभिन्नताएं हो सकती हैं । परन्तु सामान्यतः भारत में किसानों को अनेक कठिनाइयाँ झेलनी पड़ीं । वे सदा दूसरों की दया पर निर्भर रहते थे । यहां हम किसानों की कुछ प्रमुख कठिनाइयों का वर्णन करेंगे । इससे आप उस समय के किसानों की वास्तविक दशा को समझ सकेंगे ।

बहुत से क्षेत्रों में किसान का अपनी जोती हुई ज़मीन पर कोई दख़ल अधिकार (Occupancy Right) नहीं था । ज़मींदार को उन्हें बेदख़ल करने का अधिकार था, जिसका प्रयोग वे काश्तकारों को सताने के लिए करते थे ।

- ज़मींदार को नियमित कर देने के अतिरिक्त ज़मींदार काश्तकारों को "नज़राना", "अब्वाब" और विशेष अवसरों पर अन्य उपहार देने के लिए बाध्य करते थे ।
- भू-राजस्व/भूमि किराये के भारी दबाव के कारण किसान गांव के व्यापारियों और ज़मींदारों के ऋणी हो जाते थे । ये किसानों से भारी ब्याज की दर वसूल करते थे । किसान के लिए इस ऋण जाल से बाहर निकलना कठिन था । यह ऋण पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलता रहता था ।
- प्रथम विश्वयुद्ध ने किसानों की तक़लीफ़ों को और भी बढ़ा दिया । क्योंकि अनेक क्षेत्रों में किसानों को युद्ध कोष तथा सैनिक कार्यवाहियों के लिए पैसा देना पड़ता था ।
- इस काल में अनाज की क़ीमतों में भारी वृद्धि हुई । इस महंगाई से ग़रीबों को लाभ नहीं हुआ परन्तु मध्यम वर्ग और व्यापारियों को इससे लाभ हुआ ।

इस परिस्थिति में सरकार का कर्त्तव्य किसानों की सहायता करना था । परन्तु सरकार स्वयं ज़मींदारों के पक्ष में थी । इसका कारण यह था कि देहात में सरकारी शासन की स्थिरता ज़मींदारों पर निर्भर थी । अतः अनेक कष्टों के कारण किसानों ने विद्रोहों द्वारा अपनी मुक्ति का मार्ग चुना ।

बोध प्रश्न 4

1) किसानों की मुख्य परेशानियाँ क्या थीं ? लगभग 100 शब्दों में उत्तर दीजिए ।

....

....

....

....

....

....

....

2) निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही या ग़लत है ? सही पर (√) और ग़लत पर (×) का चिन्ह लगाइये ।

   i) इस काल में पहली वार किसानों ने किसान सभाओं में अपने आपको संगठित किया । ☐

   ii) ज़मींदारों को, काश्तकारों द्वारा जोती जा रही ज़मीन से उन्हें बेदख़ल करने का अधिकार नहीं था । ☐

   iii) किसान अपनी इच्छा से "अववाब" देते थे । वे इसे देने के लिए बाध्य नहीं थे । ☐

   iv) अनाज की क़ीमतों में वृद्धि से ग़रीव किसानों को लाभ हुआ । ☐

   v) किसानों की तकलीफ़ों के प्रति सरकार का रुख़ अत्यधिक सहानुभूतिपूर्ण था । ☐

28.8 1920 के दशक के दौरान किसान आन्दोलन

इस पृष्ठभूमि में अब हम 1920 के दशक के दौरान हुए कुछ महत्वपूर्ण किसान आन्दोलनों की चर्चा करेंगे । इस काल में किसान आन्दोलन का मज़वूत केन्द्र यू. पी. था । उत्पीड़क ताल्लुक़ेदारी और ज़मींदारी व्यवस्था ने किसानों का जीना दूभर कर दिया था । राष्ट्रवादियों ने किसानों की समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया । लेकिन वावा रामचन्द्र ने ज़मींदारों के विरुद्ध अवध के किसानों को संगठित करने के लिए पहल की । वावा रामचन्द्र महाराष्ट्रियन ब्राह्मण थे । वे 1905 में क़रारवद्ध श्रमिक के रूप में फिजी गये थे । वहां से वे 1917-18 में अवध लौट आए । सन्यासी की वेशभूषा में वे किसानों के वीच रहे । उन्होंने गांव में सभायें आयोजित कीं और गांव में किसानों को जागृत और संगठित करने के लिए रामचरितमानस का उपयोग किया । उन्होंने किसानों को वतलाया कि किस प्रकार सरकार और ताल्लुक़ेदारों ने उन्हें वंधुआ मज़दूर वना दिया है । दासता को तभी समाप्त किया जा सकता है जव वे एकतावद्ध होकर अपना संगठित दल वना लें । अगस्त, 1920 में अंग्रेज़ सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया तव असंख्य किसानों ने कचहरी-प्रांगण में एकत्रित होकर उनकी रिहाई की मांग की ।

1920 में किसान आन्दोलन कांग्रेस के असहयोग आन्दोलन से जुड़ गया । 1921 में किसान आन्दोलन तीव्र हो उटा और यू. पी. के रायबरेली, फ़ैज़ाबाद और सुल्तानपुर में फैल गया । किसानों ने प्रदर्शन किये । उनकी मांग थी कि ज़मीन से वेदखली रोकी जानी चाहिए । उन्होंने ज़मींदारों और महाजनों के घरों पर धावे वोले । 6 जनवरी, 1921 में किसान फ़ुरसतगंज वाज़ार में इकट्ठे हुए । उन्होंने अनाज और कपड़े की क़ीमत में वृद्धि, वनियों के भारी मुनाफ़े और ताल्लुक़ेदारों की मनमानी (निरंकुशता) के विरुद्ध विद्रोह किया । पुलिस किसानों को तितर-वितर करने में असफ़ल रही और उन पर गोली चलायी । इस कार्रवाई में 6 व्यक्ति मारे गये । 7 जनवरी को जव हज़ारों किसान रायवरेली में मुंशीगंज पुल पर इकट्ठे हुए उस समय पुलिस ने निहत्थे किसानों पर फिर गोली चलायी । नेहरूजी ने अपनी आत्मकथा में इस घटना का वर्णन इस प्रकार किया है—

"जैसे ही मैं नदी के पास पहुँचा, दूसरी ओर से गोली चलने की आवाज़ सुनी जा सकती थी । मुझे पुल पर रोक लिया गया..................इस गोलीकांड में कई लोग मारे गये थे" ।

1921 में स्थिति में परिवर्तन हुआ । सरकार की दमनकारी नीति, कांग्रेसियों के आन्दोलन को रोकने के प्रयास और 1921 में अवध लगान ऐक्ट (Ovadh Rent Act) में सुधार के कारण आंदोलन फीका पड़ गया । परन्तु इससे किसानों को शांत नहीं किया जा सका । 1921 के अंत और 1922 के आरंभ में हरदोई, वारावंकी, सीतापुर आदि ज़िलों में आन्दोलन फिर से उभरा । इन ज़िलों में किसानों ने "एका" आन्दोलन आरम्भ किया । इसे शुरू करने में जुझारू (Radical) किसान नेता

मदारीपासी का हाथ था । उनके नेतृत्व में शुरू किए गये आन्दोलन ने ज़मींदारों और प्रशासन को गंभीर चुनौती दी । तथापि अंग्रेज़ सरकार की दमनकारी नीति के कारण यह आन्दोलन असफल हो गया । परन्तु मदारीपासी को गिरफ़्तार नहीं किया जा सका ।

उत्तर बिहार में किसान आन्दोलन स्वामी विद्यानन्द के नेतृत्व में विकसित हुआ । इस क्षेत्र में दरभंगा के राजा के पास विस्तृत संपदा थी । उसने यहां के स्थानीय किसानों का विभिन्न प्रकार से दमन किया । स्वामी विद्यानन्द ने दरभंगा के राजा के विरुद्ध किसानों को संगठित किया । लेकिन यहां का आन्दोलन यू.पी. की भांति जुझारू नहीं था ।

बंगाल के किसानों ने भी "कर न देने" संबंधी आंदोलन में भाग लिया । मिदनापुर ज़िले में यह अधिक तीव्र था । किसानों ने यूनियन बोर्ड को 'कर देने' से इन्कार कर दिया । यह आंदोलन इतना प्रभावशाली था कि यूनियन बोर्ड के सदस्यों को त्यागपत्र देना पड़ा । सरकार ने यूनियन बोर्ड को समाप्त करने का निश्चय किया । इस प्रकार यह आन्दोलन सफल हुआ ।

कांग्रेस ने गुजरात में किसानों को संगठित करने का प्रयत्न किया । 1927 में कपास के मूल्य में गिरावट आने के बावजूद सरकार ने बारदोली में राजस्व बढ़ा दिया । बल्लभ भाई पटेल और कनवर जी मेहता ने किसानों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी । इस प्रकार 1928 में बारदोली सत्याग्रह आरंभ हुआ । किसानों ने सरकार को राजस्व देने से इन्कार कर दिया । इसके परिणामस्वरूप सरकार ने दमनकारी रुख़ अपनाया और किसानों की ज़मीनें ज़ब्त कर लीं । अंत में सरकार को समझौता करना पड़ा और राजस्व की दर घटा दी गयी ।

उपरोक्त आन्दोलनों के अतिरिक्त देश के अन्य भागों में भी छुटपुट विद्रोह हुए । राजस्थान, मालाबार, उड़ीसा, आसाम तथा अन्य प्रान्तों में भी किसानों ने अपने प्रति हुए अन्यायों का ज़ोरदार विरोध किया ।

28.9 1930 के दशक में किसान आन्दोलन

1930 के दशक में भी किसानों ने विभिन्न प्रांतों में विद्रोह किए । यू.पी. में किसान विद्रोह सबसे अधिक प्रभावशाली था । कांग्रेस ने 'कर न देने' संबंधी आंदोलन का आह्वान किया और ज़मींदारों से सरकार को राजस्व न देने के लिए कहा । परंतु कुछ नेता 'लगान बंदी' (No Rent) आंदोलन आरंभ करना चाहते थे । 'लगान बंदी' आंदोलन क्या है ? यह उन काश्तकारों का आंदोलन है, जो ज़मींदारों को लगान देते थे, कर नहीं आंदोलन सरकार के विरुद्ध था जबकि लगान बंदी आंदोलन का प्रभाव ज़मींदारों पर पड़ा । 1931 में लगान बंदी आंदोलन आरंभ किया गया जिसका काश्तकारों ने ज़ोरदार समर्थन किया । उन्होंने ज़मींदारों को लगान देना बंद कर दिया । आंदोलन रायबरेली, इटावा, कानपुर, उन्नाव और इलाहाबाद में फैल गया । रायबरेली के कालका प्रसाद जैसे नेताओं ने किसानों से सभी प्रकार की अदायगी रोक देने का अनुरोध किया । सरकार ने आंदोलन को दबाने का प्रयत्न किया । किसान यूनियन को अवैध घोषित कर दिया गया । आंदोलन कुचल दिया गया ।

बंगाल और बिहार में किसानों ने कर नहीं आंदोलन में भाग लिया । बंगाल में कृषक महिलाएं भी इस आंदोलन में शामिल हुईं और उन्होंने मिदनापुर ज़िले में गैर क़ानूनी नमक भी बनाया और बेचा। पुलिस द्वारा उनकी पिटाई की गयी । मानभूम, सिंहभूम और दिनाजपुर ज़िलों में आदिवासी किसानों ने नमक सत्याग्रह में भाग लिया और जेल गये परंतु ज़मींदारों को लगान का भुगतान न करने का कोई आंदोलन नहीं हुआ था ।

मद्रास में भी किसान आन्दोलन का विकास हो रहा था । 1928 में आन्ध्र रैयत एसोसिएशन बनायी गयी थी । इसके नेता प्रोफेसर एन.जी. रंगा थे । रैयत एसोसिएशन ने किसानों की तात्कालिक मांगों की तरफ़ ध्यान आकर्षित किया । इनकी महत्वपूर्ण मांगों में से एक मांग लगान में कमी थी । जिससे ज़मींदार प्रभावित हुए । जब सविनय अवज्ञा आन्दोलन आरम्भ हुआ, उस समय किसानों ने गांवों में सभाएं आयोजित की और भू-राजस्व के विरुद्ध प्रचार किया । तंजौर, मदुरा और सेलम में विद्रोह तेज़ हुआ । 1931 के अंत तक कुछ ज़िलों में अनाज के लिए दंगे आरम्भ हो गये । कृष्णा ज़िले में एक महाजन के घर पर धावा बोला गया और उसका अन्न भंडार लूट लिया गया । गुन्टूर ज़िले

पुलिस और किसानों के बीच संघर्ष हुआ । सरकार और कांग्रेस द्वारा, किसान आन्दोलन को रोकने के प्रयासों के बावजूद भी यह और अधिक उत्साह के साथ बढ़ता रहा ।

28.10 ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना

1920 तक विभिन्न क्षेत्रों में प्रान्तीय किसान सभाओं की स्थापना हो चुकी थी । परन्तु समाजवादियों और कम्युनिस्टों ने यह महसूस किया कि किसानों का एक केन्द्रीय संगठन होना आवश्यक है । उनके प्रयत्नों से 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना हुई । 1937 तक ऑल इंडिया किसान सभा की शाखाएं विभिन्न प्रान्तों में बन गईं । एन. जी. रंगा, स्वामी सहजानंद, नरेन्द्र देव, इन्दुलाल याग्निक और बंकिम मुकर्जी ऑल इंडिया किसान सभा के कुछ प्रमुख नेता थे । किसान सभा के निम्नलिखित उद्देश्य थे :

- आर्थिक शोषण से किसानों की रक्षा ।
- ज़मींदारी और ताल्लुकेदारी के रूप में भूस्वामित्व की समाप्ति ।
- राजस्व और लगान में कमी,
- ऋण स्थगन,
- महाजनों को लाइसेंस देना (महाजनों के लिये क़ानून बनाना),
- खेतिहर मज़दूरों के लिए न्यूनतम मज़दूरी,
- व्यापारिक फसलों के लिए उचित मूल्य, और
- सिंचाई सुविधाएं आदि ।

CONGRESS SOCIALIST: KISAN SUPPLEMENT.

The All India Kisan Conference

A conference of representatives of Kisan organisations of different provinces was held at Meerut on January 16th, 1936 under the presidentship of Shrimati Kamla Devi. The conference appointed a committee to organise the All-India Conference at Lucknow with a view to foster, co-ordinate, guide and help the various provincial and other local organisations and to generally strengthen the Kisan movement in the country.

The All-India Kisan Conference, was accordingly held at Lucknow on 11th and 13th April under the presidentship of Swami Sahajanand the leader of the Kisan movement in Behar. More than one thousand delegates and visitors attended the conference. The representatives of the All Bengal Peasants' Federation, the Punjab Peasants' Ryots' Association, the U. P. Kisan Sa... Relief Committee, the ... South Indian Federation of Pea... ers, the Peasants ... Malabar, the ... and the K... Gujerat, C... deliber...

agrarian problem which was the most complicated in India.

RESOLUTIONS

III. The object of the Kisan movement is to secure complete freedom from economic exploitation and the achievement of full economic and political power for the peasants and workers and all other exploited classes.

The main task of the Kisan Movement shall be the organisation of peasants to fight for their immediate political and economic demands in order to prepare them for their emancipation from every form of exploitation.

The Kisan Movement stands for the achievement of ultimate economic and political power for the producing masses through its active participation in the national struggle for winning complete independence.

ZEMINDARI SYSTEM MUST GO!

And whereas the Zamindars etc., rack-rent and oppress their crores of tenants while ... fleecing the irrigation sources.

All such systems of landlordism shall be abolished, and all the rights over such lands be vested in the cultivators.

The Zemindari system was the root of all the trouble and he was determined to press for its complete abolition. He concluded ...

This conference protests against the arrest and detention of Syt. Subhash Chandra Bose our distinguished patriot and hopes that he will very soon be set at liberty to carry on our national struggle for freedom.

"With a view to presenting in proper form the demands and grievances of the impoverished peasants of Bengal before the Bengal Land Revenue Commission, the Conference calls upon all progressive organisations in the province to co-operate with the District, Sub-divisional and Primary Congress Committees in launching a country-wide campaign.

Issued by the All India Kisan Sabha

Bombay, Feb.

16. अखिल भारतीय किसान सभा के सम्मेलन की अखबारों में रिपोर्ट ।

सभाओं और प्रदर्शनों में किसान सभा इन मांगों से किसान को अवगत कराती थी और इन मांगों की स्वीकृति के लिए सरकार पर दबाव डालती थी । ऑल इंडिया किसान सभा ने फ़ैज़पुर में अपनी दूसरी वार्षिक सभा में प्रस्ताव रखा, "देश की सारी साम्राज्यवाद विरोधी शक्तियाँ ख़ासकर किसान और मज़दूर शोषकों के ख़िलाफ़ अपने संघर्ष को तेज़ करें । यह संघर्ष शोषण के प्रतिनिधि अंग्रेज़ सरकार, ज़मींदारों, भूमिपतियों, उद्योगपतियों और महाजनों के ख़िलाफ़ होगा ।" ऑल इंडिया किसान सभा ने कांग्रेस से अलग होकर संघर्ष करने का निर्णय लिया । उन्होंने दावा किया कि किसानों की मुक्ति उनके अपने संगठन के द्वारा ही हो सकती है ।

किसान सभा ने एक नये तरीक़े का आंदोलन चलाया । यह मुख्यतः ज़मींदारों के विरुद्ध था । 1937-38 में बिहार में एक जन आंदोलन आरंभ हुआ । यह आंदोलन **बकाश्त** के नाम से विख्यात हुआ । **बकाश्त** का अर्थ है—स्वयं का जोता हुआ । प्रायः ज़मींदार **बकाश्त** भूमि से काश्तकार को बेदख़ल कर देते थे । 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल के गठन के पश्चात् किसान सभा ने **बकाश्त** के मुद्दे को उठाया । **बकाश्त** आंदोलन के दौरान किसानों ने बेदख़ली के विरुद्ध संघर्ष किया । ज़मींदार और किसानों के बीच भी संघर्ष हुआ ।

बंगाल में भी किसान सभा सक्रिय थी । वर्दवान ज़िले में दामोदर नहर के निर्माण के पश्चात् किसानों पर 'नहर कर' लगाया गया । किसान सभा ने 'नहर कर' में कमी के लिए सत्याग्रह किया । सरकार ने किसान सभा की कुछ मांगें स्वीकार कर लीं, अतः आंदोलन समाप्त कर दिया गया । उत्तर बंगाल के ज़िलों में **'हाट' 'टोला'** आंदोलन आरंभ किया गया । मेलों और हाटों में (साप्ताहिक बाज़ार) चावल, धान, सब्ज़ी, पशु बेचने वाले किसानों से ज़मींदार वसूली (Levy) करते थे । किसानों ने इस वसूली का भुगतान करने से इंकार कर दिया । कभी-कभी ज़मींदार किसानों के साथ समझौता कर लेते थे और ग़रीब किसानों को लेवी के भुगतान से छूट दे देते थे ।

1939 में बटाईदारों (Share Croppers) का आंदोलन हुआ । ये ज़मींदार की भूमि जोतने वाले ग़रीब किसान हुआ करते थे जो उत्पादन का कुछ भाग ज़मींदार को देते थे, फिर भी पट्टेदारी की कोई सुरक्षा नहीं थी और ज़मींदार इन्हें बेदख़ल कर सकता था । 1939 में काश्तकार खेत से फसल अपने खलिहानों में ले गये । इससे पहले उन्हें फसल को ज़मींदार के अन्न-भंडार में ले जाना पड़ता था, जहां उसकी गहाई की जाती थी और तब बटाईदारों और ज़मींदारों के बीच बांटा जाता था । उत्तर बंगाल के दीनाजपुर ज़िले में आंदोलन तेज़ था । सरकार ने किसानों से समझौता किया । यह निश्चित किया गया कि भविष्य में धान एक ऐसे स्थान पर इकट्ठा किया जायेगा जिसका निर्णय ज़मींदार और बटाईदार करेंगे । इस प्रकार आंदोलन सफल हुआ और किसान, संगठन क्षमता से अवगत हुए । इस काल में उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश में भी इसी प्रकार के संघर्ष हुए । आन्ध्र प्रदेश में किसानों को संगठित करने में एन. जी. रंगा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी ।

28.11 कांग्रेस और किसान वर्ग

अब हमारे ज़हन में दो प्रश्न उठते हैं, वे इस प्रकार हैं—किसान आंदोलन के विषय में कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया थी ? और कांग्रेस द्वारा निर्देशित राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में किसानों की क्या प्रतिक्रिया थी ? कांग्रेस नेता किसानों की शक्ति से भलीभांति परिचित थे और अंग्रेज़ी राज्य के विरुद्ध संघर्ष में उनके महत्व को समझते थे । वे किसान की समस्याओं और तकलीफ़ों से चिंतित थे। यह नेहरू की टिप्पणी से स्पष्ट हो जाता है, जो उन्होंने 1937 में की थी—"भारत में सबसे महत्वपूर्ण समस्या किसानों की समस्या है । शेष सब गौण है" परन्तु कांग्रेस के वे दक्षिणपंथी जो भारतीय समाज के प्रमुख सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करते थे, भारतीय किसान की बढ़ती हुई वर्ग चेतना और ज़मींदारी उन्मूलन के लिए किसान सभा की मांग से डरे हुए थे। वे चाहते थे कि किसान साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन को शक्तिशाली बनाने में सहयोग दें, परन्तु ज़मींदारों के विरुद्ध किसानों की मांग के वे विरोधी थे । जब कभी किसानों ने ज़मींदारों के विरुद्ध संघर्ष किया, कांग्रेस नेता उन्हें रोकने का प्रयास करते थे । दक्षिणपंथियों ने किसान सभा की स्थापना को कांग्रेस संगठन के लिए एक चुनौती समझा । महादेव देसाई ने इसका तर्क देते हुए लिखा है :

"यदि किसान सभा किसानों और ज़मींदारों के बीच अन्दरूनी झगड़े पैदा करती है तो उससे कांग्रेस के उद्देश्य को हानि पहुँचेगी । कांग्रेस भलि प्रकार जानती है कि राष्ट्र को बनाने वाले विभिन्न तत्वों से किस प्रकार निपटा जा सकता है । नीतियाँ निर्धारित करना कांग्रेस का कार्य है कोई व्यक्ति या समूह धमकी या बल प्रदर्शन से कांग्रेस पर अपनी नीतियाँ नहीं थोप सकता"

KISAN BULLETIN

KISANS MARCH AHEAD

The Kisans of the United Provinces have been hit hard by recent hailstorms and showers which have ruined the rabi crops—the Zemindari terrorism continues unabated. Still Kisans are organising themselves everywhere and are preparing to march ahead.

ed by rains, congratulating Mr. Subhas Bose on his re-election as president and supporting the move to give an ultimatum to the British Government.

Rai Bareli Kisan Conference

On January 31 a district conference was held at Unchahar under the presidentship of Dr. Z. Ahmed and was attended by more than 10 000 Kisans. Messrs Harsha Dev Malaviya, Devanandan Pande and other leaders addressed the gathering. In his presidential address Dr. Ahmed explained the objects of the Kisan Sabha and its relation with the National Congress.

Munshi Kalka Prasad denounced the terrors of the local zemindars and urged Kisans to be ready to march to ...

Kisan Week at Cawnpore

Kisan Week was observed in Cawnpore district from February 1 to 8. Mr. Arjun Arora inaugurated the week and addressed a ... meetings were held throughout the district and about 2,000 members were enrolled in the Kisan Sabha.

Malabar Kisans Forge Ahead

The years 1933-34 witnessed the birth of a militant kisan movement in Malabar. The Leftists and socialists formulated the peasants demands which were adopted by the Provincial Congress Committee. A series of meetings and conferences were held in 1935-36 and the Congress election propaganda of 1936-37 gave a great impetus to the nascent kisan movement. The work of agitation was followed by organisation of taluka kisan committees in 1937. And in May last the representatives of these committees met to form the All Malabar Kisan Sabha.

Bengal Kisans On March

Jute Ordinance Protest Day on October 12—Pursuant to the instructions of the secretariat of the B. P. K. C. most of the District Kisan Committees observed the All Bengal Jute Ordinance Protest Day on 15th October. Jute growers in the districts demanded Rs. 10/- as the minimum price of raw jute and protested against the Government's new attack on the peasants and the jute workers who have protested against the 30% wage-cut due to the ordinance. A workers' delegation is going to the jute-growing districts to initiate the joint struggle of workers and peasants.

Hunger-march to Santipur—On the 2nd October last about a thousands peasants from the surrounding villages of Santipur marched in a huge procession shouting revolutionary slogans and waving the Red and the National Flags. Unprecedented scenes of enthusiasm were witnessed in the town and in the neighbouring villages when even hungry half-naked women and children came out in the street to join the Hunger-March. These peasants lost their all during the heavy floods ... Comrades ... Moitra and Amrita Mukherji addressed the ... meeting and spoke on the demands for granting urgent relief to the hungry and homeless peasantry. Rice was distributed among the hunger-marchers by the local Kisan Sabha.

Land Satyagraha In Bihar

... struggle between zamindars ... the possession of Bakasht lands has again broken out in the Barahia Tal (Monghyr District) since 10th October.

It will be remembered that when there was a struggle at this harvesting time last year and mounted police were posted there, Babu Rajendra Prasad and the Premier intervened in the matter and a compromise was arrived at according to which the zamindars promised to settle lands with the tenants or at least allow lands to them without hesitation for cultivation. But since then the zamindars (particularly of Barahia) have gone back on their word. The lands actually belong to the Kisans and they have been cultivating them since time immemorial. As the zamindars are forcibly trying to cultivate these lands for themselves the kisans are offering Satyagrah and are successfully obstructing the zamindars. More over, the lands already cultivated by the kisans are sought to be recultivated nominally by the zamindars to prove their possession. This the kisans do not allow to be done.

About two dozen mounted police along with the same number of armed force are patrolling the area. None has been arrested so far. But there has been merciless beating of the kisan pickets by the zamindars and their men and about 60 persons have received various injuries. One of them got his teeth broken by a blow. An aged woman of about 60 got serious injuries and is lying in a hospital. Even minor children have offered satyagraha successfully. Young and old, men, women and children, all are taking part in it.

GUJERAT GOES FORWARD

A meeting of the Gujerat Provincial Kisan Sabha was held at Borsad (Dt. Kaira) on Feb. 12 under the presidentship of Mr. Ramalashankar Pandya. Among those present were Messrs. D. M. Pastarkar, Indulal Yagnik ... It was announced that about 7000 members had been enrolled in the Kisan Sabha as compared to the 2500 enrolled last year.

5000 Kisans' Hunger March

About 5000 Kisans arrived at Madaripur on Feb. 13 and marched in a procession through the streets of the town in pursuance of their decision to hunger-strike in order to press the demands from Government. When the procession terminated in a meeting near the court premises, a telegram from the Premier was read in which he promised to send relief if the unconstitutional agitation was dropped. The peasants' march and success have created a great ferment among the Kisans of the Bhil area in East Madaripur.

Kisan Rally At Jalpaiguri

More than 10,000 peasants, many of whom came on foot from long distances, poured marched through Jalpaiguri town with Red and National flags and banners inscribed with Kisans' demands on the occasion of the Peasants' Rally and Provincial Conference. The Peasants' Rally was held in the Conference Pandal when Mr. Subhas Bose and Com. Bankim Mukerjee of B. P. K. S. addressed the gathering. Order was maintained by a well disciplined Kisan Volunteers' Corps at the meeting. Great enthusiasm and eagerness prevailed among the peasants who attended the Rally and the Conference.

The Peasants World

III. Minimum demands. The peasants will immediately take all possible steps to achieve the following minimum demands:—

1. Cancellation of all arrears of rent and revenue.
2. Abolition of all Land Revenue Assessment and rent from uneconomic holdings.
3. The reduction by 50 per cent of rent and revenue and also of water-rates.
4. Abolition and penalisation of all feudal and customary dues and forced labour including Begar and illegal exactions.
5. The declaration of a 5 years' moratorium for all agrarian indebtedness.
6. An immediate enquiry to be made into the extent of repayment of the principal borrowed, interest thereon and the assessment of the assets and liabilities of the peasants.
7. Freedom from arrest and imprisonment for inability to pay debts, rents and revenue.
8. Immunity from attachment for all mi-

इसके विपरीत यदि हम किसान सभा और किसान आंदोलनों पर दृष्टि डालते हैं तब हमें ज्ञात होता है कि किसी भी स्तर पर किसान नेताओं ने कांग्रेस के विरुद्ध काम नहीं किया । कांग्रेस और देश की स्वतंत्रता के लिए उसकी भूमिका पर उन्हें पूरा विश्वास था । किन्तु कांग्रेस के दक्षिण पंथियों से भिन्न, किसान नेता केवल अंग्रेज़ शासन से ही नहीं बल्कि ज़मींदारों और पूंजीपतियों के आधिपत्य से भी मुक्ति की मांग करते थे । कांग्रेसी नेतृत्व और किसान नेतृत्व के बीच मतभेद का यही मुख्य कारण था । कांग्रेस के प्रति किसानों का दृष्टिकोण 4 अक्तूबर, 1939 में दिये गये सहजानंद के भाषण से स्पष्ट हो जाता है—

"हम सब कांग्रेस से उसके जादू या रहस्य के कारण नहीं बल्कि इसलिए जुड़े हैं कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है । इसने संकटपूर्ण परिस्थितियों में ग़लत क़दम नहीं उठाये.................मुक्ति के लिए राष्ट्रीय संघर्ष की इस संकटपूर्ण परिस्थिति में संगत निर्णय लेने में हमारे सारे प्रयत्न इसके हाथ मज़बूत करने के लिए हैं" ।

बोध प्रश्न 5

1) यू.पी. (संयुक्त प्रांत) में किसान आंदोलन किस प्रकार आरंभ हुआ ।

....

....

....

....

....

2) ऑल इंडिया किसान सभा की प्रमुख मांगें क्या थीं ? लगभग पांच पंक्तियों में उत्तर दीजिये ।

....

....

....

....

....

3) अपना उत्तर एक वाक्य में दीजिये ।

   i) लगान बंदी आंदोलन क्या है ?

   ii) 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेता कौन था ?

   iii) **बकाश्त** भूमि क्या है ?

   iv) बटाईदार (Share Croppers) कौन थे ?

28.12 सारांश

भारत में श्रमिकों की दुःखद स्थिति ने ट्रेड यूनियन आंदोलन के विकास के लिए अनुकूल पृष्ठभूमि तैयार की । परन्तु श्रमिकों की अशिक्षा, भाषा, जाति और सम्प्रदाय की भिन्नता और सबसे अधिक, मालिकों के ट्रेड यूनियन विरोधी दृष्टिकोण के कारण भारत में ट्रेड यूनियनो की स्थापना में विलम्ब हुआ ।

इसके बावजूद 1920 के उपरांत ट्रेड यूनियन आंदोलन धीरे-धीरे मज़बूत होने लगा । "बाहरी व्यक्तियों" ने ट्रेड यूनियनों के विकास में सहायता की । 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एक प्रमुख घटना थी । यह ध्यान देने योग्य है कि कांग्रेसियों, कम्युनिस्टों, समाजवादियों और निर्दलीय श्रमिकों ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में मिलकर काम किया ।

1937 के पश्चात् ट्रेड यूनियनवाद का विस्तार हुआ । कांग्रेस ने प्रान्तों में मंत्रिमंडल स्थापित किये । जिससे जनता में आशाएं जागीं । और श्रमिक, ट्रेड यूनियनों में शामिल हुए तथा हड़तालों में भाग लिया । कम्युनिस्टों और समाजवादियों ने इन हड़तालों में सक्रिय भूमिका निभायी ।

टैक्स का अधिक भार, बेदख़ली का भय, भूमि पर दख़ल अधिकार (Occupancy Right) न होने, आवश्यक वस्तुओं की क़ीमतों में वृद्धि और इस अन्याय के प्रति सरकार के निष्क्रिय व्यवहार ने किसानों को विद्रोह के लिये बाध्य किया । 1920 और 1930 के दौरान भारत के विभिन्न राज्यों में अनेक किसान विद्रोह हुए । किसानों ने किसान सभाओं में अपने आपको संगठित किया और एक नये प्रकार का आंदोलन आरंभ किया । आंदोलन मुख्यतः ज़मींदारों के विरुद्ध थे । किसानों के केन्द्रीय संगठन के रूप में ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना की गयी । इस काल के किसान आंदोलनों का यह एक स्थायी प्रभाव था ।

28.13 शब्दावली

हाट-टोला : बाज़ार में व्यापारियों पर लगायी गयी लेवी ।

महाजन : वह व्यक्ति जो उधार देता है ।

मई दिवस : 1 मई का दिन विश्व भर में श्रमिक दिवस के रूप में उन श्रमिकों की यादगार में मनाया जाता है, जिनकी 1 मई 1861 को अमेरिका में पुलिस की गोलियों से मृत्यु हो गयी थी ।

दख़ल अधिकार : बिना अधिकार के ज़मीन हथिया लेना ।

दक्षिणपंथी : कांग्रेस में ऐसे नेताओं का समूह जो समाजवाद का विरोध करते थे ।

हड़ताल : कुछ मांगों को हासिल करने के लिए श्रमिकों द्वारा काम करने से इंकार करना ।

Royal Commission on Labour : अंग्रेज़ सरकार द्वारा भारतीय श्रमिकों की दशा का अध्ययन करने के लिए बनाया गया कमीशन ।

ट्रेड यूनियनवाद : मज़दूरों के संगठन बनाने और अपने हितों के लिये संघर्ष करने के अधिकार का समर्थन करने वाली विचारधारा ।

28.14 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1) श्रमिक दयनीय स्थिति में रहते थे । उनके लिए अवकाश, रोज़गार की सुरक्षा और वृद्धावस्था पेंशन की व्यवस्था नहीं थी । देखिये भाग 28.2

2) (क) नहीं (ख) हां (ग) हां (घ) हां (ङ) नहीं (च) नहीं

बोध प्रश्न 2

1) ट्रेड यूनियन श्रमिकों का संगठन है ।
देखिये उपभाग 28.3.1

2) ट्रेड यूनियन ने श्रमिकों को शोषण के विरुद्ध एक साथ मिलकर काम करने का अवसर दिया । देखिये उपभाग 28.3.1

3) कुछ व्यक्तियों ने श्रमिकों की दुःखद स्थिति को देखते हुए उनकी दशा सुधारने के लिए उन्हे संगठित किया और शिक्षित किया ।
देखिये उपभाग 28.3.2

4) आरंभिक प्रयासों के फलस्वरूप धीरे-धीरे श्रमिकों के बीच ट्रेड यूनियन का विचार लोकप्रिय होने लगा और अन्त में श्रमिकों के केन्द्रीय संगठन के रूप में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गयी ।
देखिये उपभाग 28.3.3

बोध प्रश्न 3

1) श्रमिकों की तकलीफों के कारण ट्रेड यूनियन आंदोलन श्रमिकों के बीच लोकप्रिय हुआ । बाहरी व्यक्तियों ने सभाएं आयोजित करके, याचिकायें लिखकर और अपने अधिकारों के प्रति शिक्षित करके श्रमिकों की सहायता की ।
   देखिये भाग 28.4
2) मूल्यों में वृद्धि, फैक्टरियों का बंद होना, श्रमिकों का निलम्बन आदि ।
   देखिये भाग 28.5
3) देश की अर्थव्यवस्था में सुधार, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में पुनः एकता स्थापित होना, प्रांतों में कांग्रेस मंत्रालयों की स्थापना आदि ।
   देखिये भाग 28.6

बोध प्रश्न 4

1) किसानों को दख़ल अधिकार नहीं था । ज़मीन से बेदख़ली का भय, टैक्स का अधिक भार आदि ।
   देखिये भाग 28.7
2) (i) √ (ii) × (iii) × (iv) × (v) ×

बोध प्रश्न 5

1) आपके उत्तर में ताल्लुक़ेदारों का उत्पीड़न, किसानों को संगठित करने के लिए बाबा रामचन्द्र के प्रयास और आंदोलन की प्रगति आदि सम्मिलित होने चाहिए ।
   देखिये भाग 28.8
2) आपके उत्तर में आर्थिक शोषण से किसानों की रक्षा, ज़मींदारी व्यवस्था का अंत, राजस्व और लगान में छूट आदि सम्मिलित होने चाहिए ।
   देखिये भाग 28.10
3) i) सरकार को लगान का भुगतान न करना ।
   ii) वल्लभ भाई पटेल ।
   iii) स्वयं जोती गयी भूमि ।
   iv) ग़रीब किसान, जो बंटाई के आधार पर ज़मीन जोतते थे ।

इस खण्ड के लिए कुछ उपयोगी पुस्तकें

जवाहरलाल नेहरू, *आत्म कथा,* नेहरू मेमोरियल फंड, नई दिल्ली ।
अयोध्या सिंह, *भारत का मुक्ति संग्राम,* मैकमिलन, नई दिल्ली ।
रजनीपाम दत्त, *आज का भारत,* पी. पी. एच., नई दिल्ली ।
आर. एल. शुक्ला (सं), *आधुनिक भारत,* हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, नई दिल्ली ।
सहजानन्द सरस्वती, *मेरा जीवन संघर्ष,* पी. पी. एच., नई दिल्ली—1986 ।
मन्मथनाथ गुप्त, *भगत सिंह और उनका युग,* लिपि प्रकाशन, नई दिल्ली ।
मोहन सिंह जोश, *मेरठ षड्यंत्र केस : फिरंगी सरकार कटघरे में,* पी. पी. एच., नई दिल्ली ।
झारखण्डे राय, *भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन एक विश्लेषण,* पी. पी. एच., नई दिल्ली ।